Swadesh- 05.08.2015

प्रधानमंत्री के सुझाव पर मप्र सरकार भी दे प्रोत्साहन

व्यापार संवाददाता। भोपाल

मध्यप्रदेश का शक्कर उद्योग शक्कर की वैश्विक एवं घरेलू मन्दी के चलते, शक्कर के न्यूनतम स्तर के बाजार भावों के कारण धनतंगी एवं नगद तरलता के अभाव से ग्रस्त है। गन्ने के बढ़े हुये मूल्यों के कारण कृषकों को गन्ना मूल्य भुगतान में, उद्योग को अत्यंत कठिनाईयों से गुजरना पड़ रहा है। इन परिस्थितियों के समाधान हेतु शुगर मिल्स ऐसोसिएशन के समस्त पदाधिकारियों की बैठक में इस विषय के समाधान पर गहन मंथन किया गया। अध्यक्ष हेमन्त सोनी ने बताया कि अगर समाधान समय पर नहीं किया गया तो अगले वर्ष शक्कर उद्योग शासन द्वारा घोषित एफआर.पी. रू. 230/ प्रति क्विन्टल पर भुगतान नहीं कर पायेगा। ऐसोसिएशन द्वारा प्रदेश के गन्ना आयुक्त को उपरोक्त मांगो हेतु प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया।

Patrika - 05.08.2015

मीठे का कारोबार › गिरावट से उबरी, 60 रुपए क्विंटल का उछाल

आश्वासन से मीठी हुई शक्कर

भोपाल @ पत्रिका
patrika.com/business

शक्कर की गिरती कीमतों को रोकने के लिए हाल ही में शुगर मिल वालों ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात की थी। प्रधानमंत्री के आश्वासन मिलने के बाद शक्कर में पिछले दो दिन में 50 से 60 रुपए प्रति क्विंटल की तेजी आ गई। स्थानीय बाजारों में शक्कर 2320 रुपए से 60 रुपए उछलकर 2380 रुपए प्रति क्विंटल ऊपर में बोली गई। हालांकि शक्कर के सस्ती होने के बाद भी उठाव कमजोर रहा।

बाजार में तरलता कम

चीनी मिल उद्योग का कहना है कि शक्कर की वैश्विक एवं घरेलू मंदी और न्यूनतम स्तर के बाजार भावों के कारण धनतंगी एवं नगद तरलता का अभाव बना हुआ है। गन्ने के बढ़े हुए मूल्यों के कारण कृषकों को गन्ना मूल्य भुगतान में, उद्योग को अत्यंत कठिनाईयों से गुजरना पड़ रहा है। इन परिस्थितियों के समाधान हेतु शुगर मिल्स संचालकों को एक बैठक भी आयोजित हुई, जिसमें शक्कर के दाम घटने पर चिंता व्यक्त की गई।

अगर समाधान समय पर नहीं किया गया तो अगले वर्ष शक्कर उद्योग शासन द्वारा घोषित एफआरपी 230 रुपए प्रति क्विंटल पर भुगतान नहीं कर पाएगा।

हेमन्त सोनी, अध्यक्ष मध्यप्रदेश शुगर मिल्स एसोसिएशन

Janjan Jagran 05.08.2018

प्रधानमंत्री के सुझाव पर प्रदेश सरकार भी दे प्रोत्साहन

भोपाल। मध्यप्रदेश का शक्कर उद्योग शक्कर की वैश्विक एवं घरेलू मन्दी के चलते, शक्कर के न्यूनतम स्तर के बाजार भावों के कारण धनतंगी एवं नगद तरलता के अभाव से ग्रस्त है। गन्ने के बढ़े हुये मूल्यों के कारण कृषकों को गन्ना मूल्य भुगतान में, उद्योग को अत्यंत कठिनाईयों से गुजरना पड़ रहा है। इन परिस्थितियों के समाधान हेतु शुगर मिल्स ऐसोसिएशन के समस्त पदाधिकारियों की बैठक में इस विषय के समाधान पर गहन मंथन किया गया। अध्यक्ष हेमन्त सोनी ने बताया कि अगर समाधान समय पर नहीं किया गया तो अगले वर्ष शक्कर उद्योग शासन द्वारा घोषित एफआरपी 230/ प्रति कुन्टल पर भुगतान नहीं कर पायेगा। इस समस्या के दीर्घकालीन हल के लिये कुछ उपाय सुझाये गये जिसमें बाहर से आने वाली शक्कर पर 11 प्रतिशत एन्ट्री टैक्स लगाने, टीडीएस हेतु शक्कर सीधे कारखानों से खरीदने, प्रधानमंत्री द्वारा दिये गये सुझाव अनुसार मोलेसिंस आधारित इथेनाल की इकाईयां लगाने हेतु प्रोत्साहन दिया जावे। ऐसोसिएशन द्वारा गन्ना आयुक्त को उपरोक्त मांगो हेतु प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया। बैठक में ऐसोसिएशन के अध्यक्ष हेमन्त कुमार, विवेक माहेश्वरी, किशोर वियाणी, महमूद खान, नवाब रजा, आरएल टामक, नितिन गोयल मौजूद रहे।

Star Samachar-05.08.2015

प्रधानमंत्री मोदी ने दिए सुझाव पर मध्यप्रदेश सरकार भी दे प्रोत्साहन

भोपाल। मध्यप्रदेश का शक्कर उद्योग शक्कर की वैश्विक एवं घरेलू मन्दी के चलते, शक्कर के न्यूनतम स्तर के बाजार भावों के कारण धनतंगी एवं नगद तरलता के अभाव से ग्रस्त है। गन्ने के बढ़े हुए मूल्यों के कारण कृषकों को गन्ना मूल्य भुगतान में, उद्योग को अत्यंत कठिनाईयों से गुजरना पड़ रहा है। इन परिस्थितियों के समाधान के लिए शुगर मिल्स एसोसिएशन के समस्त पदाधिकारियों की बैठक में इस विषय के समाधान पर गहन मंथन किया गया। अध्यक्ष हेमन्त सोनी ने बताया कि अगर समाधान समय पर नहीं किया गया तो अगले वर्ष शक्कर उद्योग शासन द्वारा घोषित एफ.आर.पी. रू. 230 प्रति कुन्टल पर भुगतान नहीं कर पायेगा।

इस समस्या के दीर्घकालीन हल के लिये कुछ उपाय सुझाये गये जिसमें प्रमुख है:- बाहर से आने वाली शक्कर पर पंजाब एवं आंध्रप्रदेश की तरह 11: एन्ट्री टैक्स लगाया जावे, राज्य में टीडीएस के लिए शक्कर खुले बाजार के बजाय सीधे शक्कर कारखानों से खरीदी जावे, इस बात पर जोर दिया गया कि प्रदेश में प्रधानमंत्री जी द्वारा दिये गये सुझाव अनुसार बगास आधारित को जनरेशन बिजली बनाने के लिए एवं मोलेसिंस आधारित इथेनाल की इकाईयां लगाने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा भी प्रोत्साहन दिया जाए।

Haribhoomi 05.08.2015

बाहर से आने वाली शक्कर पर 11 फीसदी एन्ट्री टैक्स लगाया जाए: सोनी

भोपाल। मध्यप्रदेश का शक्कर उद्योग शक्कर की वैश्विक एवं घरेलू मन्दी के चलते, शक्कर के न्यूनतम स्तर के बाजार भावों के कारण धनतंगी एवं नगद तरलता के अभाव से ग्रस्त है। गन्ने के बढ़े हुये मूल्यों के कारण कृषकों को गन्ना मूल्य भुगतान में, उद्योग को अत्यंत कठिनाईयों से गुजरना पड़ रहा है। इन परिस्थितियों के समाधान हेतु शुगर मिल्स ऐसोसिएशन के समस्त पदाधिकारियों ने एक बैठक में इस विषय के समाधान पर गहन मंथन किया। अध्यक्ष हेमन्त सोनी ने बताया कि अगर समाधान समय पर नहीं किया गया तो अगले वर्ष शक्कर उद्योग शासन द्वारा घोषित एफआरपी 230 रुपए प्रति क्विंटल पर भुगतान नहीं कर पाएगा। श्री सोनी ने बताया कि समस्या के हल के लिए सरकार प्रदेश में बाहर से आने वाली शक्कर पर पंजाब एवं आंध्रप्रदेश की तरह 11 फीसदी एन्ट्री टैक्स लगाएं। इस के साथ ही राज्य में टीडीएस हेतु शक्कर खुले बाजार के बजाय सीधे शक्कर कारखानों से खरीदी जाएं। इस बात पर जोर दिया गया कि प्रदेश में प्रधानमंत्री द्वारा दिये गये सुझाव अनुसार बगास आधारित को जनरेशन बिजली बनाने हेतु एवं मोलेसिंस आधारित इथेनाल की इकाईयां लगाने हेतु प्रदेश सरकार द्वारा भी प्रोत्साहन दिया जाएँ। अध्यक्ष हेमन्त सोनी ने बताया कि ऐसोसिएशन द्वारा प्रदेश के गन्ना आयुक्त को उपरोक्त मांगो हेतु प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया। बैठक में ऐसोसिएशन के विभिन्न शक्कर उद्योगपति विवेक माहेश्वरी, किशोर वियाणी, महमूद खान, नवाब रजा, आरएल टामक, नितिन गोयल एवं सहकारी कारखानों के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे।

- प्रदेश के शकर निर्माताओं पर गहराया भुगतान संकट

People Smachar 05.08.2018

सुगर मिल्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों की बैठक

भोपाल। मध्यप्रदेश का शक्कर उद्योग शक्कर की वैश्विक एवं घरेलू मंदी, शक्कर के न्यूनतम स्तर के बाजार भावों के कारण धनतंगी एवं नगद तरलता के अभाव से ग्रस्त है। गन्ने के बढ़े मूल्यों के कारण कृषकों को गन्ना मूल्य भुगतान में उद्योग को अत्यंत कठिनाई हो रही है।

इन परिस्थितियों के समाधान के लिए शुगर मिल्स ऐसोसिएशन के सभी पदाधिकारियों की बैठक में इसके समाधान पर मंथन किया गया। अध्यक्ष हेमंत सोनी ने बताया कि अगर समाधान समय पर नहीं किया तो शक्कर उद्योग शासन द्वारा घोषित एफआरपी 230 रुपए प्रति क्विंटल पर अगले वर्ष भुगतान नहीं कर पाएगा। इस दौरान दीर्घकालीन हल के लिए उपाय सुझाए गए। इसमें कहा गया कि बाहर की शक्कर पर पंजाब एवं आंध्रप्रदेश की तरह 11 प्रतिशत एंट्री टैक्स लगाया जाए। राज्य में टीडीएस हेतु शक्कर खुले बाजार के बजाय सीधे कारखानों से खरीदी जाए।